दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, रविवार 01 मार्च 2020 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 153

महत्वपूर्ण एवं खास

केवीआईसी प्रदर्शनी में 22 लाख के उत्पादों की हुई बिक्री

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत 16-29 फरवरी 2020 के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवाईआईसी) कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित एक प्रदर्शनी में 22 लाख रुपये की बिक्री दर्ज की गई। प्रदर्शनी में जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की केवीआईसी इकाइयों और सीओआईआर बोर्ड द्वारा खादी के कपड़े, हस्तशिल्प उत्पाद, अचार, शहद, बाजरे के बिस्कुट, चमड़े के सामान, कढ़ाई आदि के पच्चीस स्टाल लगाए गए। प्रदर्शनी का उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल आर. के. माथुर ने किया और आज समापन समारोह में एमएसएमई मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुधीर गर्ग उपस्थित थे। प्रदर्शनी के दौरान एमएसएमई मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती अलका अरोड़ा, केवीआईसी एवं मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में लोगों ने स्टालों का दौरा किया। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद प्रभावित महिलाओं द्वारा सिले हुए खादी के रुमालों की जमकर बिक्री हुई।

म्यांमार के राष्ट्रपति, प्रथम महिला भी करेंगे ताजमहल का दीदार

आगरा (आरएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप की ऐतिहासिक यात्रा के बाद, शनिवार को ताजमहल का दीदार म्यांमार के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी करेंगे। पर्यटकों के लिए 17वीं सदी का मशहूर स्मारक शनिवार दोपहर बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सुपरिटेन्डिंग आर्कियोलॉजिस्ट वसंत स्वर्णकार ने कहा कि म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंत और प्रथम महिला डौ चो चो शनिवार को ताजमहल का दौरा करेंगे। खेरिया हवाई अड्डे से ताजमहल के पूर्वी द्वार तक की वीआईपी सड़क की सफाई की गई है और सुरक्षाकर्मियों द्वारा यातायात को व्यवस्थित किया गया है। म्यांमार के राष्ट्रपति चार दिन की भारत यात्रा पर आए हुए हैं और वह बुधवार को नई दिल्ली पहुंचे थे।

जेयूएफ के चार उग्रवादियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 महिलाएं भी शामिल

कोलकाता (आरएनएस)। जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट के चार उग्रवादियों को हावड़ा शहर के गोलाबाड़ी इलाके से शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया. इन उग्रवादियों में दो महिलाएं भी शामिल हैं. कोलकाता पुलिस के विशेष कार्यबल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को नकली भारतीय नोट के बड़े जखीरे के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था। उसने हावड़ा में अपने ठिकाने की जानकारियों का खुलासा किया जिसके बाद इन चारों को पकड़ा गया. जेयूएफ मणिपुर का उग्रवादी समूह है जो नगालैंड-मणिपुर सीमा पर सक्रिय है। अधिकारी ने बताया कि चारों जेयूएफ उग्रवादियों के पास से 34,54,270 रुपये की राशि जब्त की गई. उन्होंने यह रूपये सिम्प्लेक्स के प्रोजेक्ट मैनेजर अवजीत धार को मणिपुर के नोनी जिले से 19 फरवरी को अगवा करने के बाद एकत्र करने की बात बताई. इन चारों उग्रवादियों में से दो असम से और दो मणिपुर से हैं।

मोदी ने पूर्व पीएम मोरारजी देसाई को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मोरजी देसाई को उनकी 124वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, उन्होंने हमेशा अनुशासन और सिद्धांतों पर आधारित राजनीति की, जिसके लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। गुजरात के बुलसार जिले में 1896 में जन्म देसाई मार्च 1977 से जुलाई 1979 के बीच प्रधानमंत्री रहे थे। जनता पार्टी नेता ने इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री पद संभाला था।

» बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास » पूरे देश में 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का शुभारंभ

बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे बड़े शहरों को उपलब्ध सुविधाओं से जोड़ेगा:मोदी

चित्रकूट (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार चित्रकूट में 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे की आधारशिला रखी। यह एक्सप्रेस-वे फरवरी 2018 में घोषित उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के निर्माण की स्वीकृति का द्योतक है। 14,849 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस एक्सप्रेस-वे से चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा जिलों को लाभ मिलने की आशा है। इस कार्यक्रम के दौरान ही आज चित्रकूट में संपूर्ण देश के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का शुभारंभ भी किया गया। प्रधानमंत्री ने पीएम-किसान योजना के तहत सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के वितरण के लिए परिपूर्णता अभियान भी चलाया।

देश में रोजगार सृजन के लिए कई तरह की पहल करने के लिए सरकार की प्रशंसा करते हुए, मोदी ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे अथवा प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस-वे से न केवल उत्तर प्रदेश में संपर्क बढ़ेगा बल्कि रोजगार के कई अवसर पैदा होने के साथ-साथ यह लोगों को बड़े शहरों में उपलब्ध सुविधाओं से भी जोड़ेंगे। भूमि प्रणालियों, जहाजों और पनडुब्बियों से लेकर लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, हथियार और सेंसर जैसी रक्षा उपकरणों की व्यापक आवश्यकताओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के बजट में उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारे के लिए 3700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारे को भी गति मिल रही है। देश के किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए, प्रधानमंत्री ने 10,000 एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठनों को स्थापित करने की एक योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि किसान जो अब तक उत्पादक थे, वह अब एफपीओ के माध्यम से व्यवसाय भी करेंगे। किसानों के लिए सरकार द्वारा की गई कई पहलों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों के हित से जुड़े हर क्षेत्र पर कार्य किया है। इसमें एमएसपी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, यूरिया की 100 प्रतिशत नीम कोटिंग और दशकों से अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाएं को पूर्ण करना शामिल है। एफपीओ किसानों के प्रयासों को एक दिशा में लाने में मदद करेगा ताकि वे अपनी उपज की बेहतर मूल्य पर बिक्री कर सकें।

टीएमसी अपने कोटे से पीके को भेज सकती है राज्यसभा

नईदिल्ली (आरएनएस)। जदयू से निष्कासित नेता प्रशांत किशोर राजनीतिक रूप से बिहार में सक्रिय होना चाहते हैं, लेकिन वह अपनी संसदीय राजनीति की शुरुआत पश्चिम बंगाल से कर सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस प्रशांत किशोर को राज्यसभा में अपने कोटे से भेज सकती है। इस संदर्भ में जल्द ही फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही है। पश्चिम बंगाल में अगले महीने होने वाले राज्यसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व नए चेहरों को मौका देगी। जानकारी के मुताबिक, चार सीटों पर उम्मीदवारों का चयन लगभग कर लिया गया है। पांचवीं सीट पर उम्मीदवार के बारे में पार्टी ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है।

विधानसभा में सीटों के वितरण के लिहाज से राज्यसभा की चार सीटें तृणमूल को मिलेंगी, लेकिन पांचवीं सीट पर माकपा-कांग्रेस और तृणमूल-कांग्रेस का कोई उम्मीदवार जीतेगा। खाली हो रही पांच सीटों में से चार सीटों पर फिलहाल जोगन चौधरी, मनीष गुप्ता, अहमद हसन इमरान और केडी सिंह हैं। ये चारों तृणमूल से हैं। पांचवीं सीट पर ऋब्राब्रत बनर्जी हैं, जो 2014 में माकपा की उम्मीदवार के तौर पर निर्वाचित हुए थे, लेकिन पार्टी ने 2017 में उन्हें निकाल दिया था। तृणमूल सूत्रों की मानें तो एक को छोड़कर बाकी तीनों उम्मीदवारों की जगह पार्टी नए चेहरे उतार सकती है।

सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी महिलाओं के नाम पर 11 चेयर्स की घोषणा की

नईदिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर कल सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में युवा महिलाओं को प्रोत्साहन, महिला सशक्तिकरण और युवा महिला अनुसंधानकर्ताओं को उचित पहचान देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट भारतीय महिलाओं के नाम पर 11 चेयर्स की घोषणा की है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं और इस वर्ष के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के विषय 'विज्ञान में महिलाएं' के अनुरूप प्रस्तावों की घोषणा की है।

इन 11 चेयर्स को कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, प्रतिरक्षा विज्ञान, फाइटोमेडिसिन, जैव रसायन, चिकित्सा, सामाजिक विज्ञान, भू-विज्ञान और मौसम विज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित, भौतिकी और मौलिक अनुसंधान सहित अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में गठित किया गया है। गठित की गई चेयर्स में से एक विख्यात मानव विज्ञानी डॉ. इरावती कर्वे के नाम पर भी है।

आसनसोल स्टेशन पर पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च

» बाबुल सुप्रियो ने किया उद्घाटन

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारतीय रेल ने आसनसोल रेलवे स्टेशन पर अपने यात्रियों और वहां के आम लोगों के उपयोग के लिए अपना पहला रेल भोजनालय रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स शुरू किया। केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने 26 फरवरी, 2020 को आसनसोल स्टेशन पर आयोजित एक कार्यक्रम में अपने तरह के इस पहले रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। बाबुल सुप्रियो ने दो नए वातानुकूलित विश्राम गृह, इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण चार्ट डिस्प्ले सिस्टम (सांसद स्थानीय विकास कोष के माध्यम से) और आसनसोल स्टेशन पर बैटरी संचालित कार का भी उद्घाटन किया। आसनसोल स्टेशन पर इस रेस्टोरेंट को दो पुराने एमईएमई कोचों को नवीनीकृत करके विकसित किया गया है।

राजद्रोह कानून पर दिल्ली सरकार की समझ केंद्र से कुछ कम गलत नहीं:चिदंबरम

नईदिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा पर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कन्हैया कुमार एवं कुछ अन्य लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए शनिवार को दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि राजद्रोह कानून के बारे में दिल्ली सरकार की समझ गलत है।

चिदंबरम ने ट्वीट किया, राजद्रोह कानून को लेकर दिल्ली सरकार की समझ केंद्र से कुछ कम गलत नहीं है।'' उन्होंने कहा, '' मैं कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए और 120 बी के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने को पुरजोर तरीके से खारिज करता हूं।

दरअसल, दिल्ली सरकार ने राजद्रोह के एक मामले में जवाहरलाल नेहरू विविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और दो अन्य लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को मंजूरी दे दी। पुलिस ने 2016 के इस मामले में कुमार के साथ ही जेएनयू के पूर्व छात्रों उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने नौ फरवरी, 2016 को जेएनयू परिसर में एक कार्यक्रम के दौरान जुलूस निकाला था।

समाज का कर्ज चुकाने के लिए तैयार रहें:कोविंद

» केंद्रीय विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह

रांची (आरएनएस)। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने शुक्रवार को रांची में केंद्रीय विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित किया।

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि समाज सेवा के महत्व को समझना न केवल राष्ट्र निर्माण के लिए, बल्कि आत्मनिर्णय के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी को समाज का कर्ज चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक विश्वविद्यालय की स्थापना और संचालन में पूरा समाज योगदान

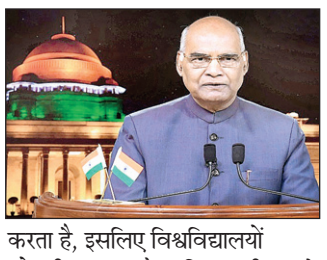

करता है, इसलिए विश्वविद्यालयों को भी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि छात्र कुछ समय आस-पास के गांवों में बिता सकते हैं और ग्रामीणों को उनकी समस्याएं हल करने में मदद और उनके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। वे ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी पहलों के बारे में जागरूक कर सकते हैं। राष्ट्रपति को यह जानकर खुशी हुई कि विश्वविद्यालय ने आसपास के पाँच गाँवों को गोद लेने की पहल की है और ग्रामीण बच्चों को पढ़ाने की ज़िम्मेदारी भी ली है। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कहा कि समाज में अपेक्षाकृत पीछे रह गए लोगों के लिए कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं।

स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड-19 पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की

नईदिल्ली (आरएनएस)। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव सचिव सुप्रीति सूदन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीडीसी) के वरिष्ठ अधिकारियों और हवाई अड्डे के सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों (एपीएचओ) के साथ कोविड-19 से बचाव एवं प्रबंधन पर उनकी तैयारियों की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन प्रतिदिन ताजा हालात, की गई कार्रवाई और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की तैयारियों की समीक्षा करते हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव ने कहा कि उभरते वैश्विक हालात को देखते हुए केंद्र के स्तर पर संबंधित मंत्रालयों और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ समन्वय करते हुए कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को उच्च सतर्कता बनाए रखने, सामुदायिक निगरानी के लिए प्रोटोकॉल के संबंध में सतर्क रहने और हवाई अड्डों एवं जांच-चौकियों पर छानबीन तेज करने की जरूरत है। उन्होंने मजबूत और प्रभावी सामुदायिक निगरानी उपायों के महत्व पर जोर दिया। इसके अलावा, उन्होंने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि रक्त के नमूनों के संग्रह और परीक्षण के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन किया जाए।

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को हवाई अड्डों पर एपीएचओ और जांच-चौकियों को मजबूत करने के लिए अपेक्षित कर्मी उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से सभी आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), मास्क इत्यादि की पर्याप्त आपूर्ति और पर्याप्त संख्या में तैयार पृथक वार्ड सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया।

केएसयू सदस्यों और गैर आदिवासियों बीच झड़प, एक की मौत

» 6 जिलों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित

शिलॉन्ग (आरएनएस)। मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और इनर लाइन परमिट (आईएलपी) पर एक बैठक के दौरान केएसयू सदस्यों और गैर आदिवासियों के बीच झड़प हो गई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। झड़प के बाद मेघालय पुलिस ने एहतियातन राज्य के छह जिलों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। बता दें कि इस झड़प को देखते हुए पहले एक रात के लिये कर्फ्यू लगाया गया था। जिसे अब हटा दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि कर्फ्यू खत्म होने के बाद भी शहर में ज्यादातर दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हैं। अधिकारियों ने बताया कि राज्य के छह जिलों पूर्वी जयंतिया हिल्स, पश्चिम जयंतिया हिल्स, पूर्वी खासी हिल्स, री भोई, पश्चिमी खासी हिल्स और दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स में शुक्रवार रात से 48 घंटों के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि सीएए विरोधी और आईएलपी के समर्थन में हुई बैठक के दौरान खासी स्टूडेंट्स यूनियन के सदस्यों और गैर आदिवासियों के बीच झड़प हो गई। यह बैठक शुक्रवार को जिले के इचामति इलाके में हुई थी।

देश के विकास के लिए विशाल समुद्री तटों का लाभ उठाएं:नायडू

ममल्लापुरम (आरएनएस)। उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने शनिवार को बंदरगाहों के सभी अध्यक्षों और प्रशासकों से बंदरगाहों को अधिक ऊर्जा सक्षम और पर्यावरण के अनुकूल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए इस तरह के प्रयासों की जरूरत है।

शिपिंग मंत्रालय द्वारा ममल्लापुरम में आयोजित की जा रही 'चिंतन बैठक' के दौरान प्रमुख बंदरगाह ट्रस्टों के अध्यक्षों के साथ बातचीत करते हुए उपराष्ट्रपति ने देश के सतत विकास के लिए विशाल समुद्र तटों का दोहन करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

भारत के विकास की कहानी में देश के 7516 किलोमीटर लंबे तट, इसके 12 प्रमुख बंदरगाहों और 200 गैर-प्रमुख बंदरगाहों के योगदान की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के पास बंदरगाह के जरिए विकास के लिए अच्छे मौके हैं क्योंकि निर्यात और आयात के लिए बंदरगाह जरूरी हैं।

इस अवसर पर नायडू ने केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किए गए सागरमाला बंदरगाह के जरिए विकास की भी सराहना की और कहा कि यह ग्रीनफील्ड बंदरगाह बनाने, मौजूदा बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और रोजगार के अवसर पैदा करके तटीय समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में सबसे अच्छा कदम है।

उन्होंने बंदरगाहों को अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए अपने वित्तीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने की सलाह दी। इसके लिए उन्होंने संचालन लागत एवं ड्रेजिंग खर्च कम करने और जहाज में माल लादने और उतारने में लगने वाले समय में बचत करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि हमें तटों के दोनों ओर अधिक पोतांतरण केन्द्र (ट्रांसशिपमेंट हब) बनाने की जरूरत है। उन्होंने तटीय सामुदायिक विकास को बंदरगाह के जरिए विकास का एक अनिवार्य घटक बताते हुए सभी प्रशासकों और प्रबंधकों को सीएसआर गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और स्थानीय युवाओं को कौशल प्रदान कर उन्हें रोजगार हासिल करने लायक बनाते हुए स्थानीय समुदायों का ध्यान रखने को कहा। उपराष्ट्रपति ने बंदरगाहों को स्वच्छ भारत जैसे कार्यक्रमों में सक्रिय रुप से भाग लेने और शहर की स्वच्छता बनाए रखने में स्थानीय अधिकारियों को सहयोग देने का आग्रह किया।

शिपिंग मंत्रालय द्वारा तटीय शहर ममल्लापुरम में तीन दिवसीय 'चिंतन बैठक' (28 फरवरी से 01 मार्च, 2020 तक) आयोजित की जा रही है। यह बैठक बंदरगाहों की विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा करने एवं उनका समाधान ढूंढने और बंदरगाहों के विकास की संभावनाओं को तलाशने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।